an>

title: Issue regarding non-payment of wages to Indian workers in Saudi Arabia.

**श्री ओम बिरला (कोटा) :** सभापति महोदय, सऊदी अरब में सऊदी-बिन-लादेन निर्माण कम्पनी के अंदर भारतीय मूल के 70 हजार कामगारों को उस कम्पनी ने छंटनी करके निकाल दिया है। इन 70 हजार कामगारों को पिछले आठ महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उनके बच्चों की फीस, खाने की रोटी और रहने का इंतजाम नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं इन कामगारों को एग्जिट वीज़ा भी दे दिया गया है। मेरी सरकार से मांग है कि भारत सरकार के सऊदी अरब में जो काउंसलर हैं, वह सऊदी अरब में जाकर मिलें, उन कामगारों को वेतन दिलाने का काम करें और उस कम्पनी के खिलाफ वहां की सरकार के नियमों के तहत कार्रवाई करें क्योंकि उन 70 हजार कामगारों में से 25 हजार राजस्थान के हैं और राजस्थान के एक प्रमुख अखबार में यह खबर छपी है और यह बहुत ही चिंता की बात है कि किस तरीके से विदेशों में हमारे कामगारों के साथ अनजस्टिस किया जाता है और अवांछित और गलत तरीके से छंटनी करके एग्जिट वीजा दिया जाता है। इस सब की जांच होनी चाहिए और वहां की सरकार के कानून के तहत कार्रवाई की जाए।

HON. CHAIRPERSON: The hon. Minister wants to respond.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी,

श्री सुधीर गुप्ता,

श्री पी.पी. चौधरी,

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत,

कुँवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री जगदम्बिका पाल,

श्री शरद त्रिपाठी को श्री ओम बिरला द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** महोदय, इस विÂाय के बारे में कई माननीय सांसदों ने भी सरकार का ध्यान आकृष्Âट किया है और कई सारे मेल्स इस बारे में माननीय सांसदों के पास आ रहे हैं, जो इस प्रकार की घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। श्री ओम बिरला, जो कोटा, राजस्थान से सांसद हैं, ने वेतनभोगी कामगारों की जो चर्चा की है, इस पूरे विÂषय के बारे में मैं विदेश मंत्रालय के पास जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजूंगा और जो भी इस बारे में आवश्यक कार्रवाई होगी, चूंकि अंतर्राÂट्रीय मामला है और सऊदी अरब की सरकार से संबंधित है। इसलिए संबंधित मंत्रालय से बात करके जो भी उचित कदम होगा, हम उसको उठाने का प्रयास करेंगे।